

Result Mitra Daily Magazine

G-7 history, 50th summit and challenges

G-7-

इतिहास-

- G-7 की उत्पत्ति 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों विशेषकर 1973 में उत्पन्न हुए वैश्विक तेल संकट के दौरान 5 देशों के वित्त मंत्रियों के अनौपचारिक बैठक से हुई।
- इन 5 देशों में फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, USA, जापान एवं ग्रेट ब्रिटेन शामिल था।
- वर्ष 1975 में फ्रांस के नेतृत्व में 5 देशों ने रामबौइलेट (फ्रांस) में वैश्विक तेल संकट पर विस्तृत चर्चा की।
- वर्ष 1975 में इन 5 देशों ने इटली को शामिल कर G-6 यानि Group of 6 का गठन किया, जिसका उद्देश्य आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए मंच बनाना था।
- वर्ष 1976 में कनाडा को शामिल कर G-7 बना और G-7 की पहली औपचारिक बैठक USA के नेतृत्व में प्यूरटोरिको में आयोजित की गई।
- यूरोपीय यूनियन हालांकि G-7 का सदस्य नहीं है लेकिन वर्ष 1981 से G-7 की बैठकों में भागीदारी करता रहा है।
- वर्ष 1997 में रूस को शामिल कर G-8 बना, लेकिन रूस द्वारा क्रीमिया पर अधिकार कर लेने के बाद वर्ष 2014 में रूस को इस समूह से निष्कासित कर दिया गया और पुनः यह G-7 बन गया।

वैश्विक महत्व-

- G-7 के देश विश्व के आर्थिक महाशक्तियों में शामिल हैं।
- वैश्विक GDP में इन देशों का योगदान लगभग 45% है, जबकि जनसंख्या में 10% का योगदान देते हैं।



चर्चा में क्यों?

- 13 जून से शुरू हो रहे 50 वें G-7 की शिखर बैठक की अध्यक्षता इटली कर रहा है।
- यह शिखर सम्मेलन 13-15 जून के बीच इटली के अपुलिया क्षेत्र में बोर्गो इग्राजिया रिसॉर्ट में आयोजित की रही है, जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुख शामिल होंगे।
- इटली 7 वीं बार G-7 की अध्यक्षता कर रहा है।
- 48 वाँ G-7 शिखर बैठक जर्मनी में आयोजित की गई थी जबकि 49 वाँ जापान में आयोजित हुआ था।
- G-7 के शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रति वर्ष की जाती है तथा अध्यक्षता का चयन सदस्य देशों के बीच Rotation system (बारी-बारी से) द्वारा निर्धारित होता है।
- G-7 का सदस्य बनने के लिए कोई औपचारिक का मानदंड का निर्धारण नहीं है।

आउटरीच देश-

- वर्ष 2003 से G-7 में आउटरीच सदस्यों की शिखर बैठकों में आमंत्रण दिया जाने लगा, जिसमें मुख्यतः एशिया एवं अफ्रीका के विकासशील देशों को निमंत्रित किया जाता है।

- इस बार के शिखर सम्मेलन में भारत सहित 11 देशों को निमंत्रण भेजा गया है। इन देशों में ब्राजील, अर्जेंटीना, मिस्र, मॉरिटानिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, केन्या एवं संयुक्त राष्ट्र संघ शामिल है।

भारत की भागीदारी-

- यह 11वां मौका होगा, जब भारत G-7 की बैठक में आउटरीच देश के रूप में भाग लेगा।
- इससे पूर्व भारत 2003 (फ्रांस), 2005 (UK), 2006 (रूस), 2007 (जर्मनी), 2008 (जापान), 2009 (इटली), 2019 (फ्रांस), 2021 (UK), 2022 (जर्मनी) एवं 2023 (जापान) की अध्यक्षता में इसमें भाग ले चुका है।
- महत्वपूर्ण तथ्य यह है की सभी बैठकों में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया है।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यह 5 वीं बैठक होगी।

ऐसा बार के प्रमुख मुद्दे-

- इंडो- पेसिफिक क्षेत्र और चीन की बढ़ती शक्ति
- जलवायु परिवर्तन
- शरणार्थी समस्या
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
- रूस यूक्रेन युद्ध

50 वां सम्मेलन और चुनौतियां-

- इस सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को दिए रहे सहायता को दोगुना करने तथा चीन की बढ़ती राजनीतिक एवं आर्थिक महत्वाकांक्षा को संतुलित करने के लिए एक मत होना सबसे प्रमुख मुद्दों में है।
- G-7 नेताओं ने रूस की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज का उपयोग का यूक्रेन के लिए 50 बिलियन डॉलर के ऋण के लिए सहमति प्रकट की है।
- पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेन्स्की बैठक में हिस्सा लेंगे।
- इस बैठक के दौरान जेलेन्स्की एवं जो बाइडेन एक दीर्घकालिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं जिसके बारे में USA के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस के लिए यूक्रेन के सहयोगियों के सामने लंबे वक्त तक टिकना संभव नहीं है।

चीन पर प्रहार-

- रूस के प्रतिबंधों को तीव्र करते हुए USA ने चीन के उन कंपनियों पर भी निशाना साधा है जो रूस को सेमीकंडक्टर उत्पाद बेचती है।
- हाल ही में USA ने चीन पर नए प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें चीन की कंपनियां शामिल हैं।
- 1 महीने पूर्व USA ने चीन के इलेक्ट्रिक वाहनों पर अतिरिक्त शुल्क को चौगुना बढ़ाकर 100% कर दिया था, अब यूरोपीय आयोग ने घोषणा की है कि जुलाई से वह चीनी आयातित EV पर 38.1 % का अतिरिक्त शुल्क लगाएगा।

सदस्य देशों के प्रमुख की चुनौतियां-

- अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति का चुनाव संभावित है और कुछ दिन पहले ही जो बाइडेन के पुत्र हंटर बाइडेन अवैध रूप से बंदूक खरीदने के लिए नशीली दवाओं के उपयोग के संबंध में झूठ बोलने के दोषी पाए गए थे।
- 4 जुलाई को यूके में चुनाव होने वाले हैं जिसमें ऋषि सुनक की स्थिति खराब बताई जा रही है।
- फ्रांस एवं जर्मनी के नेता भी राजनीतिक संकटों से गुजर रहे एवं जापान तथा कनाडा के प्रधानमंत्रियों के लिए जनमत निराशाजनक रहा है।
- सिर्फ इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इस मामले में सकारात्मक स्थिति में हैं।